

स्वतंत्रता का भ्रमः कड़ी संघर्ष से जीते अधिकारों से भू-राजनीतिक वफादारी के नाम पर दमन तक

“स्वतंत्रता का भ्रम तब तक बना रहेगा जब तक उसे बनाए रखना लाभदायक रहेगा। जिस बिंदु पर यह भ्रम बनाए रखना बहुत महंगा हो जाएगा, वे बस मंच की सजावट हटा देंगे, पर्दे पीछे खींच लेंगे, मेज और कुर्सियाँ हटा देंगे और आप थिएटर की पीछे की ईटों की दीवार देखेंगे।”

ये शब्द, 1970 के दशक के अंत में प्रतिष्ठित संगीतकार और सामाजिक आलोचक फ्रैंक ज़ाप्पा से जुड़े हुए हैं, लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की नाजुकता के बारे में गहन नास्तिकता को व्यक्त करते हैं। ज़ाप्पा का रूपक सुझाता है कि स्वतंत्रता के तत्व—बोलने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने और विरोध करने की—स्वाभाविक या शाश्वत नहीं हैं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रदर्शित तत्व हैं जो केवल तब तक बनाए रखे जाते हैं जब तक वे नियंत्रण, लाभ या स्थिरता के व्यापक हितों की सेवा करते हैं। जब असहमति इन आधारों को खतरे में डालती है, तो मुखौटा गिर जाता है और नीचे छिपी तानाशाही व्यवस्था उजागर हो जाती है। चल रहे गाज़ा संकट और पश्चिमी लोकतंत्रों में इसके प्रभावों के संदर्भ में, ज़ाप्पा की अंतर्दृष्टि भयानक रूप से पूर्वानुमानित लगती है। यह निबंध जांच करता है कि मानव अधिकार, प्रबुद्ध राज्यों से दयालु उपहार होने के बजाय, सदियों के क्रूर संघर्ष से गढ़े गए हैं; कैसे जर्मनी, यूके, यूएस, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा जैसे पश्चिमी राष्ट्रों ने प्रो-फिलिस्तीन सक्रियता को दबाने के लिए इन अधिकारों को बढ़ाते हुए निलंबित या त्याग दिया है; कैसे यह घरेलू दमन कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है; और अंत में, कैसे गाज़ा संघर्ष ने पश्चिमी सरकारों और मीडिया की इजारायल के प्रति अटूट समर्थन—जर्मनी की स्टाट्सरेज़ॉन सिद्धांत से उदाहरणित—को अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर प्राथमिकता देने को उजागर कर दिया है।

गढ़ी गई नींवें: संघर्ष और बलिदान से मानव अधिकारों का इतिहास

आज पश्चिमी लोकतंत्रों में जैसा हम समझते हैं मानव अधिकार, उदार शासकों द्वारा दिए गए अमूर्त आदर्श नहीं हैं बल्कि अत्याचार, असमानता और दमन के खिलाफ निरंतर लड़ाइयों के घावों वाली विरासतें हैं। उनका विकास सहसान्धियों पुराना है, लेकिन आधुनिक ढांचा दार्शनिक जागरणों, क्रांतियों और जमीनी आंदोलनों की टेपेस्ट्री से उभरा है जिन्होंने अनिछुक सत्ताओं से रियायतें छीनीं। सबसे शुरुआती मील के पत्थरों में से एक जिसका अक्सर जिक्र होता है वह 539 ईसा पूर्व का साइरस सिलिंडर है, एक प्राचीन फारसी कलाकृति जिसमें विजित क्षेत्रों में धार्मिक सहिष्णुता और गुलामी की समाप्ति को बढ़ावा देने वाले आदेश अंकित हैं, हालांकि इतिहासकारों के बीच इसे “मानव अधिकार चार्टर” के रूप में व्याख्या विवादित है। यह कलाकृति प्रतीक है कि अधिकार कुलीनों के लिए विशेषाधिकार नहीं बल्कि सार्वभौमिक हो सकते हैं।

मध्ययुगीन यूरोप में, 1215 का मैग्ना कार्ट अंग्रेजी बैरनों और राजा जॉन के बीच निर्णायक टकराव का प्रतीक था, जिसमें उचित प्रक्रिया और मनमाने शाही शक्ति पर सीमाओं जैसे सिद्धांत स्थापित किए गए—सिद्धांत जो सशस्त्र विद्रोह और बातचीत से छीने गए थे न कि शाही कृपा से। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल ने इन विचारों को बढ़ावा दिया, जॉन लॉक, जीन-जैक्स रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मानवता के लिए अंतर्निहित बताया, जो ईश्वरीय अधिकार वाली राजशाहियों को चुनौती देते थे। इन दर्शन ने अमेरिकी क्रांति (1775–1783) और फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799) को प्रेरित किया, जहां उपनिवेशवादी और नागरिक उपनिवेशीय शोषण और निरंकुशता के खिलाफ उठे। यू.एस. स्वतंत्रता की घोषणा (1776) ने “अविभाज्य अधिकारों” की घोषणा की, जबकि फ्रांस की मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा (1789) ने समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित किया—दस्तावेज जो रक्तपात, गिलोटिन और साम्राज्यों के पतन से जन्मे।

फिर भी ये शुरुआती विजयें अधूरी थीं, अक्सर महिलाओं, गुलामों और स्वदेशी आबादी को बाहर रखती थीं। 19वीं सदी में गुलामी विरोधी आंदोलनों ने देखा, जैसे यू.एस. में फ्रेडरिक डगलस और हैरियट टबमैन जैसे नेताओं द्वारा ट्रांसअटलांटिक गुलामी विरोध, जो गृहयुद्ध (1861–1865) और 13वें संशोधन में समाप्त हुआ। यूके और यू.एस. में सुfragettes ने

गिरफ्तारियाँ, जबरन खाना खिलाना और सार्वजनिक तिरस्कार सहते हुए महिलाओं के मताधिकार को सुरक्षित किया, सेनेका फॉल्स कन्चेशन (1848) और 1913 की महिला मताधिकार जुलूस जैसे अभियानों से, जो यू.एस. में 19वें संशोधन (1920) और यूके में आंशिक मताधिकार (1918) तक ले गए। 20वीं सदी ने वैश्विक युद्धों और उपनिवेशवाद विरोध के बीच इन संघर्षों को तीव्र किया। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की भयावहताओं ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र में एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (UDHR) को प्रेरित किया, जिसमें बोलने, एकत्रित होने और मनमाने गिरफ्तारी से सुरक्षा की स्वतंत्रताएँ संहिताबद्ध की गई। यह ऊपर से दिया उपहार नहीं था; यह यूरोप भर में एंटी-फासिस्ट प्रतिरोध आंदोलनों को प्रतिबिबित करता था, जहां पक्षपातियों और नागरिकों ने नाजी कब्जे के खिलाफ भारी कीमत पर लड़ाई लड़ी।

युद्धोत्तर युगों में नागरिक अधिकार आंदोलनों ने प्रणालीगत नस्लवाद का सामना किया: यू.एस. में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अहिंसक अभियानों ने पुलिस कुत्तों, पानी की बौछारों और हत्याओं का सामना किया, जो नागरिक अधिकार अधिनियम (1964) और मताधिकार अधिनियम (1965) तक ले गए। यूरोप में, श्रम हड़तालें, अल्जीरिया और भारत में एंटी-कॉलोनियल विद्रोह, और फ्रांस के मई 1968 छात्र विद्रोह जैसे ने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को विस्तार दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संधि (1966) को प्रभावित किया। हाल ही में, LGBTQ+ अधिकार स्टोनवॉल दंगों (1969) और एड़स सक्रियता से आगे बढ़े, जबकि स्टैंडिंग रॉक (2016) जैसे स्वदेशी आंदोलन पर्यावरण और भूमि अधिकार उल्लंघनों के खिलाफ चल रहे संघर्षों को उजागर करते हैं। पूरे इतिहास में, ये अधिकार “दिए” नहीं गए बल्कि हड़तालों, मार्चों, बहिष्कारों और कभी-कभी सशस्त्र प्रतिरोध से छीने गए—यह याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रताएँ सत्ता से रियायतें हैं, जो असुविधाजनक होने पर वापस ली जा सकती हैं।

अधिकारों का क्षरण: प्रो-फिलिस्तीन असहमति पर पश्चिमी लोकतंत्रों का दमन

एक कटु विडंबना में, वे राष्ट्र जो इन कड़ी जीती स्वतंत्रताओं का प्रचार करते हैं, हाल के वर्षों में इजरायली नीतियों की आलोचना को चुप कराने के लिए इन्हें प्रभावी रूप से निलंबित या त्याग चुके हैं, विशेष रूप से अक्टूबर 2023 से बढ़ते गाजा संघर्ष के बीच। यह दमन, मानव अधिकार संगठनों द्वारा दस्तावेजित, अत्यधिक पुलिसिंग, कानूनी अतिरेक और वैध विरोध को चरमपंथ या यहूदी-विरोध से जोड़ने से प्रकट होता है, जो खुलासा करता है कि स्वतंत्रताएँ राज्य हितों से संरेखण पर सर्वानुभव हैं।

जर्मनी इस प्रवृत्ति का उदाहरण है, जहां अधिकारियों ने प्रो-फिलिस्तीन प्रदर्शनों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे हिंसक दमन हुए हैं। 2025 में, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने जर्मनी की “पुलिस हिंसा और दमन की निरंतर पैटर्न” की निंदा की, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मनमाने गिरफ्तारियाँ, शारीरिक हमले और “नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन आजाद” जैसे नारों का अपराधीकरण शामिल है। बर्लिन कोर्ट ने नवंबर 2025 में अप्रैल में एक प्रो-फिलिस्तीन सम्मेलन बंद करने को गैरकानूनी बताया, फिर भी ऐसे हस्तक्षेप जारी हैं, जिसमें निर्वासन और एकजुटता समूहों के लिए फंडिंग कटौती शामिल हैं। लेप्ट पार्टी ने इस “दमन” को समाप्त करने का आग्रह किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तानाशाही रेंगने की चेतावनियों की गूंज में।

यूके ने पब्लिक ऑर्डर एक्ट (2023) जैसे कानूनों के तहत आतंकवाद-विरोधी शक्तियों का विस्तार किया, जिससे 2024 में अकेले “आपत्तिजनक” सोशल मीडिया पोस्टों के लिए 9,700 से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें से कई फिलिस्तीन समर्थन से संबंधित। प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिरासतें होती हैं, प्रो-फिलिस्तीन मार्चों में सैकड़ों गिरफ्तारियाँ आतंकवाद आरोपों से, फिलिस्तीन एकशन जैसे समूहों के खिलाफ। ह्यूमन राइट्स वॉच और बिग ब्रदर वॉच इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठंडा करने वाला बताते हैं, पीटरलू नरसंहार जैसे ऐतिहासिक संघर्षों से जीते अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था पर।

यू.एस. में, 2023-2025 में कैप्स एंकेपमेंट्स पर 3,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं, पुलिस द्वारा रासायनिक उत्तेजक और निर्वासन की धमकियाँ इस्तेमाल की गईं। फ्लोरिडा जैसे राज्य एंटी-जियोनिज्म को यहूदी-विरोध के बराबर मानते हैं, समूहों की जांच करते हैं और अनुबंधों में BDS भागीदारी प्रतिबंधित करते हैं, अकादमिक स्वतंत्रता के खिलाफ कानूनों का हथियार बनाते हैं।

फ्रांस ने उर्जेंस पालेस्तीन जैसे सामूहिकों को आतंकवाद-विरोधी बहानों से भंग किया, रैलियों पर 500 से अधिक हिरासतें और नए बिल जो “आतंकवादी समर्थन” या इजरायल के अस्तित्व से इनकार को अपराधी बनाते हैं। एमनेस्टी इनकी व्यापक

दमन के रूप में आलोचना करता है, अल्जीरियाई युद्ध काल से असहमति दबाने की राज्य की इतिहास की गूंज।

नीदरलैंड्स ने 2024 एम्स्टर्डम हिंसा के बाद “यहूदी-विरोधी” व्यक्तियों—अक्सर गाज़ा आलोचकों के लिए कोड—से पासपोर्ट छीनने का प्रस्ताव दिया और समिदौन जैसे समूहों पर प्रतिबंध। एक नए टास्कफोर्स ने प्रदर्शन प्रतिबंधों को जन्म दिया, जर्मनी की गिरावट की नकल।

कनाडा के शहरों जैसे टोरंटो में बायलॉ प्रदर्शन स्थलों को प्रतिबंधित करते हैं, विश्वविद्यालय दमन और संघीय धरके “चरमपंथी” समूहों पर प्रतिबंध के लिए, अधिकार और स्वतंत्रताओं के चार्टर का उल्लंघन। FIDH के अनुसार, ये पश्चिम में फिलिस्तीन एकजुटता में विरोध के अधिकार पर “निरंतर हमला” दर्शाते हैं।

दमन के समानांतर: पश्चिमी नागरिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की स्थिति की गूंज

यह घरेलू क्लैपडाउन पश्चिमी नागरिकों—विशेषकर प्रो-फिलिस्तीन आंदोलनों में—को आंतरिक “अन्य” के रूप में मानता है, उन्हें निगरानी, हिंसा और मनमाने हिरासत में डालता है जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के अनुभवों से समानांतर है। वहाँ, बसावटकर्ता हिंसा और सैन्य अतिरेक 2025 में नाटकीय रूप से बढ़े हैं, आतंक का शासन पैदा करते हुए जो पश्चिमी प्रदर्शनिकारी अब सूक्ष्म रूप में अनुभव करते हैं।

वेस्ट बैंक में, इजरायली बसावटकर्ता, अक्सर सैन्य समर्थन से, फिलिस्तीनी घरों और भूमियों पर हमले करते हैं, जिसमें पिटाई, आगजनी और भूमि हड्डपना शामिल है, हिंसा सर्वकालिक उच्च पर। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 रिपोर्ट “हिंसा और हिंसा के भय से” जबरन विस्थापन दस्तावेजित करती है, सेना समुदायों को घातक बल से निकालती है और बसावटकर्ता हमलों को रोकने में विफल रहती है। चेकपॉइंट्स पर मनमाने गिरफ्तारियाँ सामान्य हैं: फिलिस्तीनी अपमान, पिटाई और बिना आरोप अनिश्चित हिरासत सहते हैं, दोहरी कानूनी व्यवस्था में जहाँ बसावटकर्ताओं को दंडमुक्ति मिलती है जबकि फिलिस्तीनी सैन्य अदालतें झेलते हैं। OCHA रिपोर्ट विनाशकारी छापों, जेलों में यातना और गति प्रतिबंधों का विवरण देती हैं जो दैनिक जीवन को नष्ट करते हैं, 2025 में अकेले 500 से अधिक फिलिस्तीनियों की सेना या बसावटकर्ताओं द्वारा हत्या।

इन अन्यायों का विरोध करने वाले पश्चिमी नागरिक समान रणनीतियों का सामना करते हैं: प्रदर्शनों पर पुलिस चेकपॉइंट्स मनमाने रोक और तलाशी की ओर ले जाते हैं; अहिंसक सक्रियता पिटाई और रासायनिक हथियार सहती है, बसावटकर्ता-सैन्य सहयोग की तरह। जर्मनी और यू.एस. में डॉक्सिंग और निर्वासन धमकियाँ वेस्ट बैंक निर्वासनों की नकल करती हैं, जबकि यूके और फ्रांसीसी एकत्रित होने पर प्रतिबंध भूमि पहुंच इनकार की गूंज हैं। यह अभिसरण वैश्विक दमन को रेखांकित करता है: जैसे फिलिस्तीनी बसावट उपनिवेशवाद का प्रतिरोध करते हैं, पश्चिमी असहमत इसका साथ देने में चुनौती देते हैं, केवल उसी व्यवस्था को खतरा मानकर राज्य हिंसा का सामना करते हैं।

चक्र पूरा करना: गाज़ा का पश्चिमी प्राथमिकताओं और अधिकारों की नाजुकता का खुलासा

गाज़ा संघर्ष, इसके विनाशकारी टोल के साथ—हजारों मृत और व्यापक विनाश—ने अंततः उजागर किया है कि पश्चिमी सरकारें और मीडिया इजरायल के साथ भू-राजनीतिक गठबंधनों को अपने नागरिकों द्वारा संघर्ष से जीते अधिकारों से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। जर्मनी की स्टाट्सरेज़ॉन—इसकी “राज्य कारण” सिद्धांत जो इजरायल की सुरक्षा को होलोकॉस्ट प्रायश्चित के कारण अटूट मानता है—इसका प्रतीक है, प्रो-फिलिस्तीन आवाजों के दमन को यहूदी-विरोध से सुरक्षा के रूप में न्यायोचित ठहराता है, भले संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ इसे भेदभावपूर्ण बताते हैं। समान गतिशीलता अन्यत्र प्रचलित: यू.एस. का इजरायल को सालाना 3.8 बिलियन डॉलर सहायता घरेलू अभिव्यक्ति चिंताओं से ऊपर, जबकि यूके और फ्रांसीसी नीतियाँ नाटो और ईयू इजरायल-समर्थक रुख से संरेखित।

मीडिया पक्षपात इसे बढ़ाता है: 2025 मीडिया बायस मीटर विश्लेषण ने 54,449 लेखों में पाया कि पश्चिमी मीडिया “इजरायल” का जिक्र “फिलिस्तीन” की तुलना में कहीं अधिक सहानुभूतिपूर्ण करते हैं, इजरायली कथाओं को प्राथमिकता देते और फिलिस्तीनी पीड़ा को कम करते। अध्ययन प्रणालीगत पक्षपात उजागर करते हैं, जैसे फिलिस्तीनी मौतों को निष्क्रिय फ्रेमिंग जबकि इजरायली पीड़ितों को मानवीय बनाना, शीत युद्ध काल के पश्चिमी हित प्राथमिकताओं की गूंज। जैसे सोशल

मीडिया अनफिल्टर्ड गाज़ा फुटेज से इसका मुकाबला करता है, मुख्यधारा मीडिया की विफलताएँ—अल जजीरा द्वारा “सफेदीकरण” आरोपित—भ्रम बनाए रखने में सहभागिता उजागर करती हैं।

ज़प्पा की ईटों की दीवार यहाँ उभरती है: जब बोलने, विरोध और बहिष्कार जैसी स्वतंत्रताएँ इजरायल समर्थन को चुनौती देती हैं, तो उन्हें बनाए रखना “बहुत महंगा” माना जाता है। गाज़ा का खुलासा एक हिसाब मांगता है—क्या नागरिक अपने पूर्वजों द्वारा लड़ी स्वतंत्रताएँ पुनः दावा करेंगे, या सजावट गिरने देंगे, तानाशाही की स्थायित्व उजागर करते हुए? जवाब नवीनीकृत संघर्ष में है, कहीं भ्रम अपूरणीय न हो जाए।

संदर्भ

- Amnesty International. “Germany: Authorities Must End Repression of Palestine Solidarity.” Amnesty International, October 2025.
- Arab Center Washington DC. “Suppressing Palestine Advocacy in the West: Trends and Countermeasures.” Arab Center Washington DC, 2025.
- BC Civil Liberties Association. “Municipal Bylaws Restricting Protests in Canadian Cities.” BCCLA Reports, 2024–2025.
- Canadian Dimension. “Police Crackdowns on University Encampments: A Violation of Fundamental Freedoms.” Canadian Dimension, May 2025.
- FIDH (International Federation for Human Rights). “Western Democracies’ Sustained Attack on the Right to Protest in Solidarity with Palestine.” FIDH Report, 2025.
- Human Rights Watch. “United States: Crackdown on Campus Protests.” Human Rights Watch, 2025.
- Human Rights Watch. “West Bank: Israeli Forces and Settlers Escalate Violence and Forced Displacement.” Human Rights Watch Report, 2025.
- International Civil Liberties Monitoring Group. “Systemic Repression of Pro-Palestine Activism in Canada.” ICLMG, 2025.
- Media Bias Meter. “Analysis of Western Media Coverage of the Israel-Palestine Conflict, 2023–2025.” Media Bias Meter Study, 2025.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). “UN Experts Alarmed by Persistent Pattern of Police Violence and Suppression of Palestine Solidarity in Germany.” OHCHR Statement, October 16, 2025.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). “West Bank: Protection of Civilians Report.” OCHA, 2025.
- Zappa, Frank. Interview quotation widely attributed in collections of his statements on government and freedom, circa 1970s–1980s.